

ग्रामीण उत्थान में वित्तीय समावेशन की भूमिका: एक अध्ययन

जागृति सिंह¹ एवं डॉ० अमित कुमार राहुल²

¹ शोध छात्रा, वाणिज्य विभाग, टी०डी०पी०जी० कालेज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

² असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, टी०डी०पी०जी० कालेज, उत्तर प्रदेश, भारत

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received Aug 12, 2026

Accepted Aug 20, 2026

Published Aug 31, 2026

Keywords:

वित्तीय समावेशन

ग्रामीण समृद्धि

पूर्वांचल क्षेत्र

बैंकिंग सेवाएँ

सामाजिक-आर्थिक विकास

पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास की नींव है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र (वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर) में वित्तीय समावेशन और ग्रामीण समृद्धि के बीच संबंध को समझने के लिए किया गया है। विवरणात्मक अनुसंधान डिजाइन अपनाते हुए 450 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। परिणामों से पता चला कि बैंक खातों तक पहुंच (68%), डिजिटल भुगतान (54%), और सूक्ष्म वित्त तक पहुंच (42%) में वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन से कृषि उत्पादन में 32% वृद्धि, स्व-रोजगार में 28% सुधार, और घरेलू आय में 45% बढ़ोतरी देखी गई। परिणाम दर्शाते हैं कि वित्तीय समावेशन ग्रामीण समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष में, पूर्वांचल क्षेत्र में लक्षित वित्तीय समावेशन नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं और गरीबी कम कर सकती हैं। अध्ययन सरकारी एजेंसियों और नीति निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



Corresponding Author:

जागृति सिंह

Email: jagritiasingh@gmail.com

1. परिचय:

भारत की आर्थिक प्रगति ग्रामीण विकास पर निर्भर है, और ग्रामीण विकास वित्तीय समावेशन के बिना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में 5.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जहाँ अधिकांश लोग कृषि पर आश्रित हैं। यह क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहाँ गरीबी दर 35% से अधिक है (नाथ और सिंह, 2026)। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी लोगों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा, निवेश और अन्य वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच मिले। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है (भारती सिंह कुमेटी और कुमेटी, 2026)। पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बहुत सीमित है। इस क्षेत्र में बैंक शाखाओं की संख्या कम है, साक्षरता दर कम है, और लोगों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है। इन बाधाओं के कारण लोग अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों जैसे साहूकार, महाजन, और अन्य गैर-बैंकिंग संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं, जो ऊंची ब्याज दरें लेते हैं (कुमार और परिहार, 2026)। यह स्थिति ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास में बाधा डालती है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवाएँ मिलें, तो वे अपने व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कर सकते हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि ही मुख्य आजीविका है। किसान छोटी-मोटी जमीनें रखते हैं, और उन्हें बीज, खाद, और आधुनिक कृषि उपकरणों के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर उन्हें सस्ते दरों पर कर्ज मिले, तो वे अपनी कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वित्तीय समावेशन से महिलाएँ

भी आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। स्व-सहायता समूह और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाएँ छोटे-बड़े व्यवसाय शुरू कर सकती हैं (नेहा इरशाद खान और सिंह, 2026)। यह अध्ययन पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और ग्रामीण समृद्धि के बीच वास्तविक संबंध को समझने के लिए किया जा रहा है। अध्ययन के निष्कर्षों से नीति निर्माताओं को इस क्षेत्र में बेहतर वित्तीय नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी।

2. साहित्य समीक्षा

वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि सभी लोग चाहे वे गरीब हों या अमीर, बैंकिंग सेवाओं, बीमा, और अन्य वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकें। इसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है (प्रसाद, 2025)। भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ हुई थी, जिसका उद्देश्य सभी को बैंक खाते खुलवाना था। तब से लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा गया है (गौतम, 2026)। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ वित्तीय समावेशन पूरी तरह नहीं हुआ है, पूर्वांचल क्षेत्र उनमें से एक है। ग्रामीण समृद्धि का मतलब है गाँव के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार। इसमें बेहतर आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जीवन स्तर शामिल है। वित्तीय समावेशन से ग्रामीण समृद्धि का सीधा संबंध है क्योंकि जब लोगों को पैसा लगाने का मौका मिले, तो वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं (द्रव और अहिरवार, 2025)। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) भारत में ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ आपस में बचत करती हैं और एक दूसरे को कर्ज देती हैं (सिडाना और तिवारी, 2025)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं और कृषि तथा छोटे व्यवसायों को कर्ज देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ग्रामीण इलाकों में बैंक की शाखाएँ नहीं हैं (टांडेकर और त्रिपाठ, 2025)। डिजिटल भुगतान के विकास ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया है। जागृति सिंह (2026) के अध्ययन में पूर्वांचल क्षेत्र में डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग की चर्चा की गई है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच बढ़ने से लोग अब घर बैठे पैसे भेज सकते हैं। यह बदलाव विशेषकर गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहा है।

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और वित्तीय समावेशन किसानों के लिए बहुत जरूरी है। किसानों को फसल बोनो से पहले और बोनो के बाद विभिन्न कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। औपचारिक बैंकिंग चैनल से कर्ज मिलने पर किसान अपनी कृषि को आधुनिक बना सकते हैं (सुमित कुमार और प्रो० प्रीति पाठक, 2025)। सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को खरीफ और रबी सीजन में कर्ज देते हैं, जिससे वे अच्छी पैदावार ले सकें। बनूथ (2024) के अनुसार, ग्रामीण विकास के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और वित्तीय सेवाएँ सभी शामिल हों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में छोटे व्यवसायियों को कर्ज दिया गया है (सुनीता शर्मा और रुचि गुप्ता, 2021)। इस योजना का असर यह रहा है कि लाखों लोगों ने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है।

3. अनुसंधान उद्देश्य

1. पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना।
2. वित्तीय समावेशन के ग्रामीण समृद्धि पर सकारात्मक प्रभावों की पहचान करना।

4. अनुसंधान पद्धति

यह विवरणात्मक (डिस्क्रिप्टिव) अनुसंधान था जिसमें मौजूदा स्थिति को विस्तार से समझा गया। अनुसंधान क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के पाँच जनपद वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, और गाजीपुर थे। इन जनपदों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये क्षेत्र कृषि-प्रधान हैं और वित्तीय समावेशन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का उपयोग करते हुए कुल 450 ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया। प्रत्येक जनपद से 90 परिवार का चयन किया गया। परिवारों को तीन समूहों में विभाजित किया गया: (क) वित्तीय समावेशन से जुड़े परिवार, (ख) आंशिक रूप से जुड़े परिवार, (ग) बिल्कुल नहीं जुड़े परिवार। अर्धसंरचित साक्षात्कार और प्रश्नावली का

उपयोग किया गया। प्रश्नावली में आय, कृषि उत्पादन, बैंक खातों की जानकारी, डिजिटल लेनदेन, और व्यवसाय संबंधी सवाल थे। डेटा का विश्लेषण SPSS 26 सॉफ्टवेयर में किया गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी (प्रतिशत, औसत, मानक विचलन) का उपयोग किया गया। वित्तीय समावेशन और ग्रामीण समृद्धि के बीच संबंध जानने के लिए पीयरसन सहसंबंध का प्रयोग किया गया। आय और उत्पादन में अंतर देखने के लिए टी-टेस्ट किया गया।

5. परिणाम

तालिका 1: पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की स्थिति

वित्तीय सेवाएँ	संख्या (n=450)	प्रतिशत (%)
बैंक खाता धारक	306	68
बचत खाता	287	63.8
डिजिटल भुगतान का उपयोग	243	54
सूक्ष्म वित्त तक पहुंच	189	42
कृषि कर्ज प्राप्त	198	44
व्यवसायिक कर्ज	127	28.2

पूर्वांचल क्षेत्र में 68% परिवारों के पास बैंक खाते हैं, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। 63.8% के पास बचत खाते हैं, जो बचत की आदत को दर्शाता है। डिजिटल भुगतान का उपयोग करने वाले 54% परिवार हैं, जो डिजिटल इंडिया की सफलता को दर्शाता है। 42% परिवारों को सूक्ष्म वित्त की सुविधा मिली है। 44% किसान कृषि कर्ज ले रहे हैं, और 28.2% लोगों को व्यवसायिक कर्ज मिला है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय समावेशन का विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

तालिका 2: वित्तीय समावेशन के अनुसार कृषि उत्पादन में परिवर्तन

समावेश स्थिति	औसत वार्षिक उत्पादन (क्विंटल)	उत्पादन में वृद्धि (%)	n
पूरी तरह समावेशित	18.5	+32	155
आंशिक समावेशित	12.3	+18	168
बिल्कुल नहीं समावेशित	9.2	0	127

पूरी तरह वित्तीय समावेशन से जुड़े किसानों का औसत वार्षिक उत्पादन 18.5 क्विंटल है, जबकि बिल्कुल समावेशित नहीं किसानों का उत्पादन मात्र 9.2 क्विंटल है। यह 32% का अंतर दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन से किसान आधुनिक तरीकों को अपना सकते हैं और ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। औपचारिक बैंकिंग के माध्यम से किसान बेहतर बीज, खाद, और उपकरण खरीद पाते हैं।

तालिका 3: वित्तीय समावेशन के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय

समावेश स्थिति	औसत वार्षिक आय (हजार रुपये)	आय में वृद्धि (%)	n
पूरी तरह समावेशित	156	+45	155
आंशिक समावेशित	112	+25	168
बिल्कुल नहीं समावेशित	76	0	127

वित्तीय समावेशन से परिवारों की आय में भी काफी बदलाव देखा गया। पूरी तरह समावेशित परिवारों की औसत वार्षिक आय 156 हजार रुपये है, जो बिल्कुल समावेशित नहीं परिवारों की आय (76 हजार रुपये) का लगभग दोगुना है। यह 45% की वृद्धि को दर्शाता है। आंशिक समावेशन वाले परिवारों में 25% की वृद्धि देखी गई। अतः वित्तीय समावेशन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार स्पष्ट है।

तालिका 4: वित्तीय समावेशन और स्व-रोजगार में वृद्धि

समावेश स्थिति	स्व-रोजगार में संलग्न व्यक्ति	वृद्धि (%)	प्रमुख व्यवसाय
पूरी तरह समावेशित	98	+28	दुकान, कपड़ा, खाद्य
आंशिक समावेशित	64	+15	कृषि आधारित
बिल्कुल नहीं समावेशित	32	0	अनौपचारिक

वित्तीय समावेशन से लोग नए व्यवसाय शुरू कर पाए हैं। पूरी तरह समावेशित परिवारों में 98 व्यक्ति स्व-रोजगार में हैं, जो 28% की वृद्धि को दर्शाता है। इन लोगों ने छोटी दुकानें, कपड़ा व्यवसाय, और खाद्य पदार्थों की बिक्री का काम शुरू किया है। बिल्कुल समावेशित नहीं लोग मजदूरी या अनौपचारिक कार्यों पर निर्भर हैं। मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को स्व-रोजगार के लिए कर्ज मिला है।

तालिका 5: महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन

संकेतक	समावेशित महिलाएँ (%)	अन्य महिलाएँ (%)	अंतर (%)
स्व-सहायता समूह की सदस्य	72	28	+44
वित्तीय निर्णय में भाग	65	22	+43
व्यवसाय संचालन	58	15	+43
शिक्षा में निवेश	68	35	+33

वित्तीय समावेशन से महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 72% महिलाएँ स्व-सहायता समूहों का हिस्सा हैं, जबकि अन्य इलाकों में यह आंकड़ा मात्र 28% है। 65% समावेशित महिलाएँ घर के वित्तीय फैसलों में हिस्सा लेती हैं। 58% महिलाएँ अपना व्यवसाय चला रही हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। शिक्षा में निवेश करने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी अधिक है।

तालिका 6: वित्तीय समावेशन से जुड़ी चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	आवृत्ति (n=450)	प्रतिशत (%)
बैंक शाखा दूर होना	187	41.6
साक्षरता की कमी	165	36.7
डिजिटल ज्ञान की कमी	143	31.8
ऊँची ब्याज दरें	112	24.9
जटिल दस्तावेज प्रक्रिया	98	21.8

वित्तीय समावेशन की राह में कई चुनौतियाँ हैं। 41.6% लोगों के लिए बैंक शाखा दूर है, खासकर दुर्गम इलाकों में। 36.7% लोग अनपढ़ हैं और बैंकिंग प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। 31.8% लोगों को डिजिटल तरीकों का ज्ञान नहीं है, जो डिजिटल भुगतान में बाधा डालता है। 24.9% लोग ऊँची ब्याज दरों से परेशान हैं। ये चुनौतियाँ दूर करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

6. परिणामों की विवेचना

इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के विस्तार के साथ ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण 68% परिवारों के बैंक खाते खुल गए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है (नाथ और सिंह, 2026)। लेकिन बाकी 32% अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 46% लोग इससे दूर हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की जरूरत है। कृषि उत्पादन में 32% की वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसानों को औपचारिक बैंकिंग के माध्यम से कर्ज मिलता है, तो वे आधुनिक तरीकों को अपना सकते हैं। उन्नत बीज, रसायनिक खाद, और सिंचाई की सुविधा से पैदावार में

वृद्धि होती है (कुमार और परिहार, 2026)। आय में 45% की वृद्धि समाज के निचले तबके के लिए जीवन परिवर्तन करने वाली है। यह आय शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास में निवेश के लिए उपयोग की जा सकती है।

स्व-रोजगार में 28% की वृद्धि का अर्थ है कि लोग अब मजदूरी पर निर्भर नहीं हैं। मुद्रा योजना के तहत हजारों लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज मिला है (सुनीता शर्मा और रुचि गुप्ता, 2021)। ये व्यवसाय दुकानें, कारीगरी के काम, और सेवा क्षेत्र में हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो वित्तीय समावेशन ने महिलाओं को आर्थिक आजादी दी है। 72% महिलाएँ स्व-सहायता समूहों का हिस्सा हैं, जहाँ वे आपस में बचत करती हैं और एक दूसरे को कर्ज देती हैं (नेहा इरशाद खान और सिंह, 2026)। हालांकि, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। 41.6% लोगों के लिए बैंक दूर है, जो दूरदराज के इलाकों में एक समस्या है। बैंकों को छोटी शाखाएँ या कियोस्क खोलने चाहिए। साक्षरता की कमी एक गंभीर समस्या है, खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के बीच। स्थानीय भाषाओं में वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए। डिजिटल ज्ञान की कमी से लोग डिजिटल भुगतान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग सिखाया जाना चाहिए। ऊँची ब्याज दरें भी समस्या हैं, जो लोगों को कर्ज लेने से बचाती हैं।

7. निष्कर्ष

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वित्तीय समावेशन ग्रामीण समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिला है। बैंक खातों में 68% वृद्धि, कृषि उत्पादन में 32% बढ़ोतरी, और आय में 45% वृद्धि से साफ है कि वित्तीय समावेशन असरदार है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बैंक शाखाओं को बढ़ाना, साक्षरता कार्यक्रम चलाना, और डिजिटल शिक्षा देना जरूरी है। सरकार और स्थानीय संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बाकी 32% परिवार भी वित्तीय समावेशन से जुड़ सकें। पूर्वांचल क्षेत्र की गरीबी कम करने और समृद्धि लाने का यह एक सशक्त तरीका है।

Reference

- [1]. नाथ, ग., एवं सिंह, सी. बी. (2026). ग्रामीण उद्यमिता के विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 6(4), 775–784. <https://doi.org/10.48175/IJARST-12345>
- [2]. भारती सिंह कुमेटी, एवं कुमेटी, सुनील कुमार. (2026). छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की भूमिका. *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*, 14(1), 84–91. <https://doi.org/10.52711/2454-2687.2026.00015>
- [3]. कुमार, मुकेश, एवं परिहार, विजय सिंह. (2026). स्वयं सहायता समूहों की भूमिका महिला आर्थिक आत्मनिर्भरता में: एक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के संदर्भ में). *Journal of Emerging Trends and Novel Research*, 4(3), B634–B647.
- [4]. गौतम, च. प्र. (2026). ग्रामीण भारत के रूपांतरण में जिला प्रशासन की संस्थागत भूमिका: विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एक समालोचनात्मक अध्ययन. *Indian Journal of Modern Research and Reviews*, 4(4), 174–180. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19663439>
- [5]. जागृति सिंह. (2026). डिजिटल भुगतान प्रणाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: पूर्वांचल क्षेत्र का अध्ययन. *ResearchPro International Multidisciplinary Journal*, 2(1), 52–57. <https://doi.org/10.70650/rpimj.2026v2i100008>
- [6]. नेहा इरशाद खान, एवं सिंह, निरूपमा. (2026). बुनकर महिलाओं की बदलती सामाजिक-आर्थिक स्थिति: एक समाजशास्त्री विश्लेषण. *International Journal of Advances in Social Sciences*, 14(1), 45–48. <https://doi.org/10.52711/2454-2679.2026.00011>

- [7]. प्रसाद, डॉ. आर. (2025). भारत की परिप्रेक्ष्य से वित्तीय समावेशन और उसके ग्रामीण विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 1–7.
- [8]. द्रव, डॉ, एवं अहिरवार, देवकी. (2025). छतरपुर जिले के ग्रामीण विकास में जिला पंचायत की भूमिक. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 722–731. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-29185>
- [9]. सिडाना, र. र., एवं तिवारी, पी. एन. (2025). कुमाऊँ मण्डल में कूर्माचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड की वर्तमान स्थिति एवं कार्य प्रगति का अध्ययन. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 12(2), d716–d725.
- [10]. सुमित कुमार, एवं प्रो० प्रीति पाठक. (2025). ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums*, 4(07), 62–69.
- [11]. टांडेकर, भुवनलाल, एवं त्रिपाठ, श्वेता. (2025). भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों का अध्ययन. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 22, 110–117. <https://doi.org/10.29070/7xkjt761>
- [12]. बनूथ, वि. (2024). रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया: ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजीज, चैलेंजेस एंड द पाथ टू सस्टेनेबल ग्रोथ. *TIJER - इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल*, 11(10).
- [13]. सुनीता शर्मा, एवं रुचि गुप्ता. (2021). प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*, 3(2), 95–101.

Cite this Article:

जागृति सिंह एवं डॉ० अमित कुमार राहुल, " ग्रामीण उत्थान में वित्तीय समावेशन की भूमिका: एक अध्ययन", *Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT)*, ISSN: 3139-1656 (Online), Volume 2, Issue 8, pp. 16-21, Aug 2026.

Journal URL: <https://vijact.com>

DOI: <https://doi.org/10.65785/vijact.v2i8.88>

Disclaimer/Publisher's Note: The author(s) are solely responsible for the content of this article, including its accuracy, originality, and ethical compliance. The publisher and editors assume no liability for any errors, copyright issues, or consequences arising from its publication or use.